माननीय न्यायमूर्ति परमजीत सिंह के समक्ष

संजीव नागपाल- याचिकाकर्ता

बनाम

एटीयू एल शर्मा- *प्रतिवादी*

2013 का सीआरएमएम नंबर एम -3011

अप्रैल 12,2013

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -S.304 & 482 - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138 - धारा 138 के तहत कार्यवाही में शिकायतकर्ता। अनेक अवसरों के बावजूद अभियुक्त के वकील द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गई - आदेश द्वारा प्रतिपरीक्षा बंद - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त/रद्द कर दिया और यह कहते हुए प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी कि शिकायतकर्ता के बयान की सत्यता की जांच केवल प्रतिपरीक्षा के माध्यम से ही की जा सकती है- याचिका की अनुमति दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की जिम्नी आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न तिथियों पर, याचिकाकर्ता के वकील उपस्थित नहीं हुए, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता विभिन्न तिथियों पर अप्रकाशित रहा। निष्पक्ष सुनवाई विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आवश्यकता है जहां जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

(पैरा 9)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की मेरा विचार है कि प्रतिपरीक्षा ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा अभियुक्त अपने खिलाफ आरोप की सत्यता को सीधे चुनौती दे सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियुक्त को दिए गए मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।

(पैरा 10)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि शिकायतकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि याचिकाकर्ता को सीडब्ल्यू 1 और अन्य शिकायतकर्ता गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी जांच की जानी बाकी है। हालांकि, याचिकाकर्ता को इस संबंध में शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए लागत का बोझ डाला जा सकता है।

(पैरा 1, 1)

राजीव कटारिया। याचिकाकर्ता *के लिए वकील*

जापान यादव, अधिवक्ता, *प्रतिवादी के लिए।*

न्यायमूर्ति परमजीत सिंह

1. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत पर मामला शुरू किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को 4.40 लाख रुपये के चेक के अनादरण के लिए बुलाया गया था।

2. याचिकाकर्ता की पेशी के बाद शिकायतकर्ता गवाहों की जांच के लिए केस फिक्स किया गया। शिकायतकर्ता का मुख्य परीक्षण दिनांक 12022012 को शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और मामले को प्रतिपरीक्षा के लिए 27012012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता सीडब्ल्यू 1 की जिरह के लिए याचिकाकर्ता को कई अवसर प्रदान किए गए थे। अंततः दिनांक 12.12.2012 के आदेश में, जब याचिकाकर्ता के वकील उपस्थित नहीं थे, सीडब्ल्यू की जिरह को 'शून्य' करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता इस आदेश से व्यथित है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

3. प्रस्ताव के नोटिस के अनुसरण में, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी उपस्थित हुए और याचिका में किए गए कथनों से इनकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया और उत्तरदाताओं की मुख्य आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता से जिरह करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, लेकिन उसका वकील शिकायतकर्ता से जिरह करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसकी जिरह को सही ढंग से शून्य के रूप में दिखाया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि सीडब्ल्यू 1 पर शिकायतकर्ता ने अपना हलफनामा मुख्य परीक्षा में दिया था और उत्तरदाताओं का कोई अन्य गवाह मौजूद नहीं था। इस कारण से प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकी। उन्होंने विभिन्न तिथियों के ज़िमनी आदेशों का संदर्भ दिया है। दिनांक 15022012 के जिमनी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि कोई सीडब्ल्यू उपस्थित नहीं है और शिकायतकर्ता को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। दिनांक 28022012 और 22032012 को भी कोई सीडब्ल्यू उपस्थित नहीं था। दिनांक 12042012 को शिकायतकर्ता/सीडब्ल्यू 1 की

प्रतिपरीक्षा के लिए मामला निर्धारित किया गया था। कोई अन्य सीडब्ल्यू मौजूद नहीं था। इस तरह शिकायतकर्ता को कई अवसर दिए गए, केवल शिकायतकर्ता उपस्थित रहा लेकिन कोई अन्य गवाह उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि सीडब्ल्यू 1 की जिरह के लिए याचिकाकर्ता के वकील की ओर से चूक हुई थी, लेकिन इस कारण से याचिकाकर्ता को पीड़ित नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता को अभियुक्त होने के नाते सीडब्ल्यू से जिरह करने का अधिकार है। जिरह द्वारा परीक्षण की आवश्यकता सत्य की सत्यता मौलिक सिद्धांत है और साक्ष्य के कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अभियुक्त को शिकायतकर्ता गवाहों से जिरह करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सीडब्ल्यू की प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के लिए तथ्यों, निष्कर्षों और छापों को प्रस्तुत करने का एकमात्र अवसर है

गवाह के बयान की सत्यता पर सवाल उठाना और बचाव पक्ष की दलील स्थापित करना। इस प्रकार, जब वकील उपस्थित नहीं था, तो यह न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के लिए एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त करे, जो मुकदमे के दौरान अप्रकाशित रहता है क्योंकि जिरह करने का अवसर एक आवश्यकता है। जब मामले की सुनवाई 12122012 को की गई। याचिकाकर्ता/अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील नहीं था। इस प्रकार यह न्यायालय का विधिवत था कि वह उसके लिए कानूनी सहायता वकील नियुक्त करे। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि शिकायतकर्ता से जिरह करने का अवसर दिया जा सकता है अन्यथा याचिकाकर्ता का अधिकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। "शिकायतकर्ता को लागत के साथ मुआवजा दिया जा सकता है क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत एक अर्ध-नागरिक प्रकृति का विवाद है।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि लगभग एक वर्ष तक याचिकाकर्ता के वकील द्वारा शिकायतकर्ता की जिरह नहीं की गई। इस कारण से, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और 111ग का अवलोकन किया है।

7. दिनांक 12.12.2012 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उस तारीख को केवल सीडब्ल्यू 1 अतुल शन्ना-शिकायतकर्ता उपस्थित थे। कोई अन्य सीडब्ल्यू उपस्थित नहीं था, उसकी जिरह शून्य होने का आदेश दिया गया था और

मामले को अगली तारीख के लिए सीडब्ल्यू की परीक्षा के लिए स्थगित कर दिया गया था।

8. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जिरह क्रूसिबल है जिसमें शिकायतकर्ता साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में यह भी ध्यान रखा जाता है कि शिकायतकर्ताओं के गवाहों के टुकड़ों में साक्ष्य की आम तौर पर अनुमति नहीं है। भौतिक गवाहों को एक तारीख को पूछताछ करने की अनुमति दी गई। प्रतिपरीक्षा एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा अभियुक्त शिकायतकर्ता गवाहों की सत्यता को सीधे चुनौती दे सकता है और यह अभियुक्त के मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। जब शिकायतकर्ता की जिरह की गई तो गवाह को शून्य माना गया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। सीआरपीसी की धारा 304 के प्रावधानों के मद्देनजर, जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो अदालत को उसे राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता वकील प्रदान करने या एमिकस क्यूरी नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। मुफ्त कानूनी सहायता वकील की पात्रता अभियुक्त द्वारा इस आशय का आवेदन करने पर निर्भर नहीं है और न्यायालय अभियुक्त को मुफ्त सहायता प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है।

9. ज़िमनी आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न तिथियों पर, याचिकाकर्ता के वकील उपस्थित नहीं हुए, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता विभिन्न तिथियों पर अप्रकाशित रहा। निष्पक्ष सुनवाई विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आवश्यकता है जहां जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

10. मेरा यह विचार है कि प्रतिपरीक्षा ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप की सत्यता को सीधे चुनौती दे सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियुक्त को दिए गए मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।

11. उपरोक्त के विचार से, इस न्यायालय का विचार है कि शिकायतकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि याचिकाकर्ता को CW1 और अन्य शिकायतकर्ता गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी जांच की जानी बाकी है। हालांकि, याचिकाकर्ता को इस संबंध में शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए लागत का बोझ डाला जा सकता है।

12. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता पर 15.000/- रुपये का बोझ है, जिसमें से 2.000/- रुपये

शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे और 13,000/- रुपये याचिकाकर्ता द्वारा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में जमा किए जाएंगे।

13. पक्षकारों को दिनांक 01052013 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया। याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता-सीडब्ल्यूआई से जिरह करने का एक अवसर दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट CW1 को तलब करेगा, याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह वकील को नियुक्त करे और शिकायतकर्ता/CW 1 को उस तारीख पर जिरह करे, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किया जाना है। यदि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो न्यायालय एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त करेगा। इसके बाद, कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही जारी रहेगी।

पीएस बाजवा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।